

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 512]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 16, 1971/आश्विन 24, 1893

No. 512]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1971/ASVINA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October 1971

S.O. 3863.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance hereinafter specified:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri Durga Shankar Dave, formerly Chief Justice, High Court, Rajasthan, to inquire into the following matters, namely:—

(1) the allegations made by—

(i) Shri Trilochan Singh Riyasti in a memorandum dated the 20th July, 1971, presented to the President of India, and

(ii) Shri Satyapal Dang, in his letters dated the 5th July, 1971 and the 31st July, 1971, addressed to the Governor of the State of Punjab,

against certain former Ministers of the State of Punjab.

(2) further allegations relating to the former Ministers of Punjab that may be referred to the Commission by the Central Government.

2. The Commission will complete its inquiry and submit its report to the Central Government within a period of three months.

3. And whereas the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be

made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. 375/31/71-AVD.III.]

P. K. J. MENON, Secy.

कानूनी विभाग

(मंत्रिमंडल सचिवालय)

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 1971

अधिसूचना

का० प्रा० 3863.—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सार्वजनिक महत्व के एक विशिष्ट मामले में जिसका उल्लेख आगे किया गया है जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच-आयोग बैठाया जाना आवश्यक है :

अतः अब केन्द्रीय सरकार जांच-आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मामलों की जांच-पड़ताल करने हेतु एतद्वारा एक जांच-आयोग बैठाती है, जिसके सदस्य राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री दुर्गा शंकर दवे होंगे —

(1) वे आरोप जो—

(i) श्री त्रिलोचन सिंह रियासती ने राष्ट्रपति को दिए गए अपने 20 जुलाई 1971 के आपन में, और

(ii) श्री सत्यपाल डंग ने राज्यपाल पंजाब को लिखे अपने 5 जुलाई 1971 और 31 जुलाई 1971 के पत्रों में,

जो राज्य के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाए हैं ।

(2) पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों से सम्बन्धित वे और आरोप जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को भेजे जाएं ।

2. आयोग तीन महीने में अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे देगा ।

3. और चूंकि इस जांच-पड़ताल के स्वरूप और इस मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जांच-अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4) और उप-धारा (5) के सभी उपबन्ध इस आयोग पर लागू किए जाने चाहिए, अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त धारा की उप-धारा (2), (3) (4) और (5) के सभी उपबन्ध इस आयोग पर लागू होंगे ।

[मं० 375/31/71-ए०सी०डी—(II)]

पी० के० जे० मेनन, सचिव ।